चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/2329
दिनांक : 22.08.2025

सेवा में,

1. सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

2. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, परिसर मेरठ।

विषयः–उत्तर प्रदेश में 1 मिलियन नागरिको हेतु ए.आई. (AI) कौशल विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्याः 2209/सत्तर–3–2025 दिनांक 21.08.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्याः 424/78–2–2025–ई–1797169 दिनांक 24.04.2025 एव शासन के पत्र संख्याः 11–मु0स0/सत्तर–3–2025 दिनांक 08.05.2025 की छायाप्रति संलग्न करते हुए आर्टीफिशयल इटेंलिजेंस (**AI**) एव डाटा साइंस के विभिन्न पहलूओं से अवगत कराते हुए उत्तर प्रदेश में मिलियन नागरिकों हेतु आर्टीफिशयल इटेंलिजेंस (**AI**) के क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम को प्रभावी ढ़ग से क्रियान्वित किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 24.04.2025 में की गयी अपेक्षा अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया हैं।

उक्त के संदर्भ में शासन के सभी उपरोक्त पत्रों की छायाप्रति संलग्न करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि शासन के निर्देशों के क्रम में व्यापक कार्य योजना पर 02 कार्य दिवसों में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से विश्वविद्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

/

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

01. सयुक्त सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग–3,उ0प्र0,शासन के संज्ञानार्थ।
02. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
03. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. प्रभारी वेबसाइट इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
05. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

CIR_19 (50)

समयबद्ध
संख्या- 2209/सत्तर-3-2025

प्रेषक,
प्रेम कुमार पाडेण्य,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक**,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव**,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 21 अगस्त, 2025**

विषय- उत्तर प्रदेश में 1 मिलियन नागरिकों हेतु एआई (AI) कौशल विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या- 424/78-2-2025-ई-1797168, दिनांक 24.04.2025 (छायाप्रति संलग्न) एवं शासन के पत्र संख्या-11-मु0स0/सत्तर-3-2025, दिनांक 08.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एवं डाटा साइंस के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराते हुए उत्तर प्रदेश में मिलियन नागरिकों हेतु आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में एआई कौशल विकास कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या- 424/78-2-2025-ई-1797168, दिनांक 24.04.2025 में की गयी अपेक्षानुसार अग्रतर कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु सूचना अप्राप्त है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या- 424/78-2-2025-ई-1797168, दिनांक 24.04.2025 में दिये गये निर्देशों के क्रम में व्यापक कार्ययोजना 02 कार्य दिवस में शासन को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by
PREM KUMAR PANDEY
Date: 21-08-2025
16:25:07

भवदीय,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

Nikhil S.O.

पत्र संख्या-424/78-2-2025-ई-1797168

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(निधि श्रीवास्तव)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक: 24 अप्रैल, 2025

विषयः उत्तर प्रदेश में 1 मिलियन नागरिकों हेतु एआई (AI) कौशल विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश एक विशाल राज्य है, जहां विभिन्न प्रकार सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ विद्यमान है। वर्तमान समय में, (AI) ए.आई. (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और डेटा साइंस जैसी तकनीकों का प्रयोग न केवल शहरी क्षेत्रों में, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास के नए अवसर उत्पन्न कर रहा है। राज्य सरकार (AI) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर कार्य कर रही है। राज्य में युवाओं को AI और अन्य उभरती तकनीकों में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में विशेष पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा टेक्नोलॉजी कंपनियों, स्टार्टअप्स और शैक्षिक संस्थानों के साथ मिलकर AI प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है। इसके अलावा, विश्वविद्यालयों में अत्याधुनिक AI लैब्स और इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि छात्र इस क्षेत्र में उच्च तकनीकी ज्ञान/ शोध के साथ ही व्यावहारिक रूप से इसके लागू किये जाने वाले एप्लीकेशन्स पर भी काम कर सके। ऑनलाइन कोर्स, वर्कशॉप और सरकारी पोर्टलों के माध्यम से भी AI से जुड़ी शिक्षा को सुलभ बनाया जा रहा है। इन पहलों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाना, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और उत्तर प्रदेश को तकनीकी कौशल का एक प्रमुख केंद्र बनाना है।

इस पृष्ठभूमि में, राज्य सरकार ने AI को राज्य के हर कोने में फैलाने और सभी वर्गों को इससे सशक्त बनाने की योजना बनाई है। यह योजना राज्य में एक मिलियन लोगों को AI आधारित तकनीक के विभिन्न आयाम से परिचित कराते हुए इसके उपयोग आधारित पहलू से कौशलयुक्त करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसके द्वारा, न केवल युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि राज्य के प्रशासनिक ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, और अन्य क्षेत्रों में AI का प्रयोग बढ़ेगा जो कि राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

2- **दृष्टिकोण (Vision):** योजना का उदेदश्य AI और डेटा विज्ञान के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरना है, जो न केवल शहरी केंद्रों, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी तकनीकी सुधार लाए। राज्य का विजन यह है कि हर नागरिक – चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण – को डिजिटल और तकनीकी कौशल मिले, जो उन्हें आने वाली तकनीकी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- **मिशन (उद्देश्य):** योजना का मुख्य उद्देश्य (Misson) राज्य के एक मिलियन नागरिकों को AI के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना है। इसके माध्यम से, राज्य में डिजिटल साक्षरता और कौशल वृद्धि को बढ़ावा देना है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को न केवल रोजगार के अवसर प्राप्त हों, बल्कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में AI का प्रभावी उपयोग हो सके। यह योजना स्थानीय उद्योगों, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, और प्रशासनिक क्षेत्रों में AI के प्रयोग को बढ़ावा देगी और यह लक्षित किया जायेगा कि प्रशिक्षित व्यक्ति वास्तविक जीवन में AI का उपयोग करने में सक्षम हों, और साथ ही राज्य के विकास में योगदान करें।

4- **लक्ष्य समूह (Target Audience) :** इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के उन सभी कार्मिको और नागरिकों को शामिल किया जाएगा, जो एआई (AI) क्षेत्र में कार्य करने के लिए कौशल प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें राज्य सरकार के कर्मचारी, शिक्षक/प्रोफेसर, चिकित्सक, छात्र एवं छात्राओं, प्रोफेशनल्स, ग्रामीण अंचलों के नागरिक और वे व्यक्ति शामिल होंगे जो नए कौशल में रुचि रखते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। लक्षित समूह के रूप में निम्न प्रमुख घटकों को प्रशिक्षण दिए जाने की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जाएगी :-

•**राज्य सरकार के कर्मचारी** (Government Employees):
सरकारी कर्मचारियों को AI और डिजिटल साक्षरता के बुनियादी ज्ञान से लैस किया जाएगा, ताकि वे प्रशासनिक कार्यों में AI का सही उपयोग कर सकें।

•**शैक्षिक संस्थान** (Educational Institutions):
स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों व् छात्रों को AI के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे भविष्य में तकनीकी कौशल युक्त हों और भविष्य में अवसर की सम्भावना हेतु तैयार हों।

•**स्वास्थ्य पेशेवर** (Health Professionals):
स्वास्थ्य क्षेत्र में AI का उपयोग बढ़ाने के लिए डॉक्टरों, नर्सों, और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

•**व्यावसायिक पेशेवर** (Working Professionals):
तकनीकी और गैर-तकनीकी पेशेवरों को AI के उपयोग और उनके क्षेत्र में इसके लाभ के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा।

•**ग्रामीण जनसंख्या** (Rural Populace):
विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे, जो कृषि, ग्राम्य उद्यम, और अन्य ग्रामीण जरूरतों पर आधारित होंगे।

5- **साझेदार संस्थान** (Partnering Organizations): इस क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए AI/आई टी क्षेत्र में प्रतिष्ठित साख वाले समूह और कंपनियां और संगठन राज्य सरकार के साथ मिलकर इस योजना के क्रियान्वन हेतु सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए सहमत हुए हैं | उक्त में प्रमुख के नाम निम्नवत है:-

- Microsoft
- Intel
- Guvi (HCL)
- Wadhvani
- 1M1B

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

इन संस्थानों के सहयोग से, AI के क्षेत्र में प्रशिक्षण को अधिक सशक्त और प्रभावी बनाया जाएगा। ये संस्थान पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करने, कार्यशालाएँ आयोजित करने, और तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित करने में सहायता देंगे|

(i) उपरोक्त संस्थाओं के साथ हुए विचार विमर्श में योजनान्तर्गत आरम्भिक रूप से राज्य सरकार के कर्मचारी, शिक्षक/प्रोफेसर, चिकित्सक, छात्र एवं छात्राओं, प्रोफेशनल्स एवं ग्रामीण (प्रधान, जन सेवा केन्द्रों, प्रगतिशील किसान, स्वंय सहायता समूह) को AI के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिए जाने की रूप रेखा पर संस्थावार भूमिका के विषय में निम्नवत निर्णय लिया गया है:-

क्र0	संस्था का नाम	कार्य योजना
1	माइक्रोसॉफ्ट	1. माइक्रोसॉफ्ट द्वारा तीन प्रमुख स्तंभों – **व्यक्तित्व (Personas), भागीदारी (Partnerships) और डिलीवरी (Delivery)** के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी की जानी प्रस्तावित है। 2. प्रस्तावित योजना उपयोगकर्ताओं, डेवलपर्स और संगठन के प्रमुख को कौशल प्रदान करने पर केंद्रित होगी, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) की योजना के अनुरूप अनुकूलित किया जाएगा। 3. माइक्रोसॉफ्ट भारत में अधिक से अधिक नागरिकों को प्रशिक्षित करने की योजना बना रहा है और इसकी स्किलिंग तकनीक राज्य के डिजिटल पोर्टलों में एकीकृत की जा सकती है।
2	इंटेल	1. इंटेल द्वारा विभिन्न स्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से AI के विषय पर प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है :- o डिजिटल रेडीनेस (माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए) o AI for Citizens o AI for Youth o AI for Future Workforce o AI for Current Workforce (कर्मचारियों के लिए) o Digital Readiness for Government Leaders & Public Sector Officers 2. इंटेल द्वारा प्रदेश में छात्रों को AI विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यह कार्यक्रम **MEITY (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), CBSE और शिक्षा मंत्रालय** के सहयोग से चलाए जा रहे हैं।
3	गुवी (एच.सी.एल.)	1. प्रस्तावित योजना के तहत 3,500+ प्रशिक्षकों के माध्यम से ऑफ़लाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 2. प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र 2 दिनों का होगा, जिसमें एक बैच में 50 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		3. Guvi प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने की एक मॉडल (Train the Trainer) भी अपनाएगा, ताकि कौशल का व्यापक प्रसार हो सके।
4	वाधवानी	1. वाधवानी द्वारा **हाइब्रिड (ऑनलाइन और ऑफलाइन) मॉडल** के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है। 2. सरकारी अधिकारियों (जो प्रमुख निर्णय-निर्माता हैं) के लिए **2-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम** आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। 3. अन्य कर्मचारियों के लिए **11 मॉड्यूल्स वाला ऑनलाइन कोर्स** प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। 4. वरिष्ठ शिक्षकों को **ऑफलाइन प्रशिक्षण सत्र** में प्रशिक्षित किया जाएगा, जबकि कनिष्ठ शिक्षकों और छात्रों को **ऑनलाइन कोर्स** के माध्यम से कौशल प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इनके द्वारा Guru Mitra LMS प्लेटफॉर्म भी विकसित किया गया है।
5	1 मिलियन 1 बिलियन (1M1B)	1. 1 मिलियन 1 बिलियन (1M1B) ने **IBM, Oppo और Meta** जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी कर कौशल विकास कार्यक्रम चलाए हैं। इसके अलावा, **CBSE के साथ मिलकर स्कूल पाठ्यक्रम में AI को शामिल** किया गया है। 2. संगठन ने आंध्र प्रदेश में **एक उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence)** स्थापित किया है। इसी मॉडल पर एक केन्द्र उत्तर प्रदेश में भी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जहां पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। 3. 1 मिलियन 1 बिलियन (1M1B) द्वारा हाइब्रिड (ऑनलाइन और ऑफलाइन) मॉडल के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

(ii) AI प्रशिक्षण कार्यक्रम में तालिका में उल्लिखित उक्त संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं को भी प्रशिक्षण कराये जाने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

6- **पाठ्यक्रम संरचना:** राज्य सरकार के कर्मचारी, शिक्षक/प्रोफेसर, चिकित्सक, छात्र एवं छात्राओं, प्रोफेशनल्स, ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को निम्नवत इंडीकेटिव कोर्सेज पर प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है :-

1. **Introduction to AI and Its Applications**
- Basics of AI, machine learning, and data analytics.
- Real-world examples relevant to sectors like education, agriculture, governance, and business.

2. **AI Tools and Techniques**
- Overview of simple AI tools for automation, data analysis, and decision-making.
- Practical demonstrations tailored to the participant group.

3. **Sector-Specific Modules**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- Government Employees: Enhancing efficiency through AI-based decision systems.
- Teachers: Personalized learning tools and AI in education management.
- Students: Career opportunities and innovation using AI.
- Progressive Farmers: AI-driven crop planning, pest control, and market linkages.
- SHGs: AI applications in small business management and marketing.
- Doctors: AI applications in Medical Technologies.

4. **Ethics and Responsibility in AI**

- Ensuring ethical and sustainable use of AI technologies.

7- **प्रशिक्षण कार्यक्रम और पार्टनर संस्था** : उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यत: स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों, शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी, छात्र-छात्राएं, प्रोफेशनल्स एवं ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को निम्न संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है :-

क्र0 सं0	प्रशिक्षु	विवरण	Tentative Mapping (संस्थाओं के नाम)
1	राज्य सरकार के कर्मचारी	आई.ए.एस./पी.सी.एस. अधिकारी, जनपद, निदेशालय, कारपोरेशन, सचिवालय प्रशासन विभाग इत्यादि के कर्मचारियों।	एच.सी.एल, माइक्रोसॉफ्ट, वाधवानी फाउन्डेशन, आई.बी.एम., इंटल कारपोरेशन, 1M1B
2	शिक्षक/प्रोफेसर	बेसिक, माध्यमिक, पॉलीटेक्निक एवं आईटीआई के शिक्षक।	वाधवानी फाउन्डेशन, एच0सी0एल0, 1M1B, इंटेल कारपोरेशन
3	चिकित्सक	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी चिकित्सक।	वाधवानी फाउन्डेशन, 1M1B
4	छात्र एवं छात्राओं	तकनीकी एवं गैर तकनीकी छात्र/छात्राओं, पॉलीटेक्निक एवं आईटीआई।	इंटल कारपोरेशन, 1M1B, वाधवानी फाउण्डेशन
5	प्रोफेशनल्स	कार्यक्षेत्र से वापस हो रही महिलाओं एवं कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण।	एच.सी.एल, माइक्रोसॉफ्ट, आई.बी.एम., इंटल कारपोरेशन
6	ग्रामीण अंचल	प्रधान, जन सेवा केन्द्रों, प्रगतिशील किसान, स्वंय सहायता समूह को प्रशिक्षण।	वाधवानी फाउन्डेशन, 1M1B, एच0सी0एल0

नोट :- प्रदेश में व्यापक ए.आई. प्रशिक्षण हेतु संक्षिप्त क्रियान्वयन योजना पत्र के साथ संलग्न है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- **प्रशिक्षण विधियाँ (Training Methods):** उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों, शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी, छात्र-छात्राएं, प्रोफेशनल्स एवं ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को निम्न माध्यम / प्रकार से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा :-

- **ऑफलाइन प्रशिक्षण:** राज्य भर के सरकारी और निजी तकनीकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों, और कौशल विकास केंद्रों में उपरोक्त तकनीकी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष प्रशिक्षण (Classroom Training) प्रदान किया जाएगा।
- **जनपद स्तर पर प्रशिक्षण** का आयोजन किसानों हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र (KVK), युवाओं हेतु सेवायोजन कार्यालय, शिक्षकों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET), प्रोफेस्नल्स को डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री केन्द्र (DIC), जनपद एवं मंडल स्तर पर उपलब्ध मीटिंग/ट्रेनिंग हॉल्स जैसे स्थानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन जनपद में स्थापित डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी के साथ समन्वय करते हुये किया जायेगा।
- **लैब्स और केंद्र:** प्रदेश की तकनीकी संस्थाओं में स्थापित विशेष एआई लैब्स, कम्प्यूटर लैब, प्रशिक्षण केंद्र इत्यादि को ए.आई. प्रशिक्षण हेतु उपयोग किया जायेगा, जहाँ प्रशिक्षु परियोजना आधारित कार्य, प्रयोगशाला कार्य, और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे।

9- **समय सीमा और कार्यान्वयन (Timeline and Implementation):**

- **प्रारंभिक चरण (Initial Phase):** पहले 2 महीनों में प्रशिक्षकों की नियुक्ति और पाठ्यक्रम की तैयारी की जाएगी।
- **मध्यम अवधि (Medium Term):** योजना क्रियान्वन के तीसरे माह से राज्यभर में प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी।
- **दीर्घकालिक लक्ष्य (Long Term Goal):** यह लक्षित किया जायेगा की आगामी दिसम्बर माह तक राज्य में एक मिलियन प्रशिक्षित व्यक्तियों को AI में दक्ष किया जाएगा। इस हेतु मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से प्रतिदिन समानान्तर रूप में विभिन्न जनपदों में Multiple बैचों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसमें एक माह में 1.5 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है अर्थात अनुमानित 4 – 6 माह में 1 मिलियन से अधिक नागरिकों को ए.आई. तकनीकी विषय पर प्रशिक्षित किया जायेगा।

10- **वित्तपोषण और संसाधन:** प्रदेश सरकार निजी कंपनियों, एनजीओ और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के माध्यम से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु वित्तीय और संस्थागत समर्थन प्राप्त करेगी। साथ ही इस कार्य योजना के लिए प्रदेश सरकार भी अन्य उच्चगुणवत्ता वाले प्रस्तावों के लिए अनुदान जारी कर सकती है, जिसमें प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षकों के शुल्क और प्रमाणपत्र जारी करने की लागत शामिल होगी।

11- **समन्वय एजेंसी और विभागीय सहयोग (Departmental Collaboration):** इस अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर सेंटर फॉर ई-गवर्नेन्स (सी.ई.जी.), आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी। प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वन हेतु सम्बंधित मुख्य विभागों द्वारा सहयोग किया जायेगा जिसके लिए प्रत्येक प्रमुख विभाग अपने स्तर से स्वंय से सम्बंधित घटक और स्टेक होल्डर्स के विषय में इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु कार्यवाही

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

करेंगे। यद्यपि इस योजना में राज्य सरकार के समस्त विभागों और अधिकारीयों द्वारा सक्रिय और सकरात्मक भूमिका का निर्वहन किया जायेगा तथापि कतिपय प्रमुख विभाग जो इस विषय में कार्य करेंगे वो निम्नवत हैं :-

1	शिक्षा विभाग	स्कूलों और विश्वविद्यालयों में AI पाठ्यक्रमों का संचालन
2	स्वास्थ्य विभाग	चिकित्सकों व् स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए स्वास्थ्य तकनीक में AI का उपयोग।
3	कृषि विभाग	कृषि में AI आधारित समाधान और प्रशिक्षण।
4	ग्राम्य विकास विभाग	ग्राम विकास के कार्मिक, स्वयं सहायता समूह एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण ।
5	सचिवालय प्रशासन	समस्त सचिवालय कार्मिको के प्रशिक्षण हेतु ।
6	राजस्व विभाग	समस्त राजस्व कर्मी के प्रशिक्षण हेतु ।

12- **निगरानी और मूल्यांकन (Monitoring and Evaluation):**

राज्य स्तर पर निगरानी) State-Level Monitoring):

इस योजना की प्रगति के अनुश्रवण के लिए व कठिनाईयों के निराकरण के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होगी, जो इसका नियमित अनुश्रवण करेगी। हर महीने प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी और मूल्यांकन होगा कि किस जिले में क्या सफलता मिली है। प्रदेश स्तर पर प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग टीम की स्थापना की जाएगी, जो योजना के क्रियान्वयन, ऑपरेशनल हैंडहोल्डिंग व मॉनीटरिंग में मदद करेगी।

जिला स्तर पर निगरानी) District-Level Monitoring):

जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक जिले में कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम समय पर चल रहा है। जनपद स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

13- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्णित बिन्दुओं के क्रम में उत्तर प्रदेश में 1 मिलियन नागरिकों हेतु आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस के क्षेत्र में एआई कौशल विकास कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाना सुनिश्चित किया जाये, ताकि उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिकों को तकनीकी कौशल के क्षेत्र में अधिक से अधिक सुदृढ किया जा सके।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृष्ठांकन संख्या- 424(1) /78-2-2025 एवं दिनांक तदैवः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, विशेष सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. राज्य समन्वयक, सेंटर फॉर ई-गवर्नेन्स, लखनऊ, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. हेड, एस0ई0एम0टी0, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नेहा जैन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(संलग्नक-1)

Implementation Plan - AI Skilling Plan for 1 million citizens in Uttar Pradesh

To equip 1 million citizens in UP with AI skills, a structured and outcome-driven skilling implementation plan has been designed. This plan focuses on onboarding specialized skilling partners, integrating programs with government departments, ensuring robust training execution, and implementing a rigorous monitoring framework. A strong emphasis is placed on industry-aligned curriculum, performance-based evaluation, and sustainable funding through CSR and government contributions. The following steps outline the structured approach to achieving this vision.

1. Proposal Solicitation

- Beyond the existing empaneled skilling providers, detailed proposals will be invited and secured from specialized AI skilling partners through targeted outreach and digital platforms.

2. Evaluation and selection of skilling providers

- The IT Department will evaluate proposals evaluation based on pre-defined criteria, and consult the Skilling Advisory Committee for further assessment, if required. Post evaluation, selected skilling providers will be onboarded.

3. Departmental Coordination & Program Integration

- Meetings will be conducted between selected skilling providers and relevant govt. departments to ensure targeted implementation. For instance, providers conducting AI skilling for senior govt. officials will coordinate with the SAD. The respective department will oversee implementation and monitoring throughout the training duration.

4. Structured Training Implementation Plan Submission

Selected skilling providers will submit a comprehensive execution plan covering:

- **Infrastructure Needs:** Laptops, software, course materials, and training facilities.
- **Training Logistics:** Location and scheduling, ensuring alignment with available infrastructure
- **Curriculum Design:** Tailored AI courses for their target groups, ensuring industry relevance
- **Faculty & Trainer Details:** Number of trainers, trainer qualifications, and faculty-student ratio.
- **Program Timelines & Milestones:** Training duration, monthly targets, and learning outcomes.
- **Assessment & Certification framework**
- **Financial Plan:** Budget structure with a clear split between CSR contributions and government funding (if applicable), ensuring transparency in utilization.
- **Budget utilization and other financial metrics**
- **Performance Metrics and Organizational profile**
- **Monitoring and Evaluation approach** for tracking progress and impact

5. Baseline Assessment & Beneficiary Mobilization

- Skilling providers will conduct a pre-training baseline assessment to analyze the skill gaps of target beneficiaries and submit a detailed report to the IT Department.
- Beneficiary mobilization will be driven by training providers with support from the concerned department, and digital outreach campaigns.

6. Training Execution, Monitoring and Impact Measurement

- AI skilling sessions will be conducted as per the agreed training schedule, with weekly monitoring of key performance metrics such as attendance, completion rates, and engagement levels. Feedback loops will be established to refine training methodologies dynamically.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1 MILLION for 1 BILLION

Ms. Nidhi Srivastava IAS
Special Secretary
Department of Higher Education
Government of Uttar Pradesh

August 11, 2025

(निधि श्रीवास्तव)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उ०प्र० शासन।

Subject: Proposal for Implementation of AI Pragya Program in Higher Education Institutions across the state in collaboration with 1M1B Foundation.

Respected Madam,

The Government of Uttar Pradesh has launched the visionary AI Pragya Program to empower 10 lakh citizens of the state with future-ready skills in Artificial Intelligence. Under this initiative, our organization, 1M1B Foundation, an UN Accredited Organization, an official implementation partner of the Government of Uttar Pradesh, has been entrusted with the responsibility of engaging and training youth from schools and higher education institutions.

Through this letter, I would like to propose that the Department of Higher Education extend its kind support in enabling the implementation of this program in all higher education institutions across the state. The AI Skills Training will be organized completely free of cost, and upon successful completion, students will receive:

1. Globally recognized industry certification from our partners like EY and IBM
2. Certificate from the Government of Uttar Pradesh under the AI Pragya Initiative
3. Access to job fairs and career opportunities to connect them with potential employers

The program will follow a hybrid delivery model, combining offline activation workshops with online self-paced learning, supported by expert interactions from industry mentors. This initiative will not only equip students with essential AI knowledge but also enhance their employability and readiness for the future job market.

For your kind reference, I have attached a detailed concept note along with the Government Order issued by the Hon'ble Chief Secretary of Uttar Pradesh endorsing the AI Pragya Initiative as the annexure.

I request your kind approval and support in issuing the necessary notification for the participation of all higher education institutions in this program for the benefit of our youth.

With regards,

1M1B Foundation Bangalore

Shivam Agrawal
Sr. Manager – 1M1B
+91-9140929120

1 MILLION
1 BILLION

RAGYA

Empowering Youth in Emerging Technologies under AI Pragya initiative

In collaboration with the Government of Uttar Pradesh, 1M1B

In alignment with the visionary AI Pragya Initiative launched by the Government of Uttar Pradesh under the leadership of the Hon'ble Chief Minister shri Yogi Adityanath —to equip 10 lakh citizens with future-ready skills in Artificial Intelligence, Cybersecurity, Data Analytics, Machine Learning, and —1M1B (One Million for One Billion), an UN-accredited not-for-profit organization, has been appointed as one of the official implementation partner.

AI Pragya is a flagship program initiated by the Government of Uttar Pradesh to democratize access to digital skills and prepare the youth of the state for the AI-powered future. The program focuses on reaching students, women, farmers, and youth from underserved regions and equipping them with certifications, job-readiness, and mentorship opportunities. Learn more about AI Pragya here: https://aipragya.up.gov.in/

As part of this mission, 1M1B, as an official partner of the initiative, is pleased to offer the AI Youth Skills Program and Certification course from its partners, like EY GDS (Ernst & Young) & IBM. This initiative aims to provide youth with AI awareness, foundational knowledge, and a globally recognized certification to youth in schools, colleges, polytechnics, ITIs, and universities.

This program will enable students to understand real-world AI applications, gain career insights, and build AI skills needed to gain employment in the future. The program follows a hybrid delivery model—combining offline activation workshops at academic institutions with online, self-paced learning and insightful engagement sessions with experts from the industry.

Note: A copy of the Government Order issued by the Chief Secretary of Uttar Pradesh endorsing the AI Pragya initiative is attached for institutional reference and validation.

How an Institute Can Participate:

Institutions across Uttar Pradesh are invited to become Activation Partners in the Program by:

1. Nominating an AI Program Coordinator (faculty/staff) for smooth facilitation
2. Hosting an offline activation workshop conducted by the 1M1B team
3. Encouraging students to register and complete the online AI Skills Passport course
4. Supporting expert interaction sessions (online/offline) with industry professionals

Implementation Model:

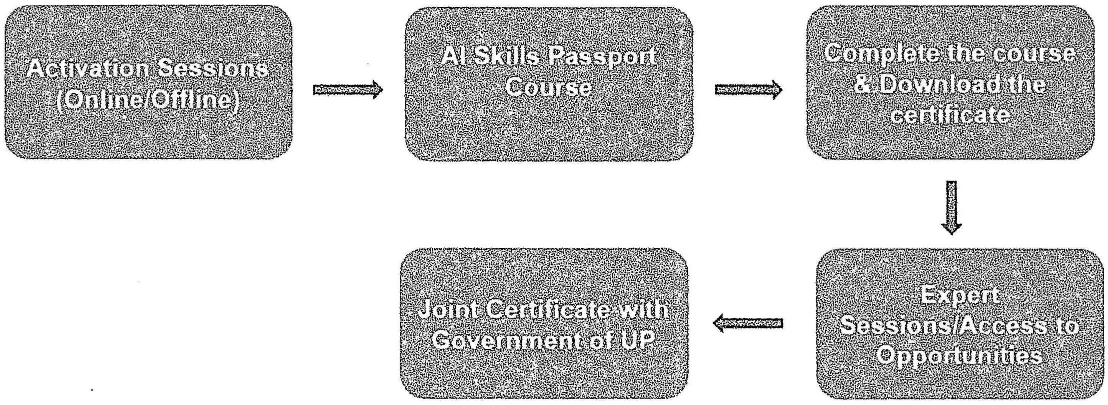

Program Details:

- Target Audience: Students
- Language: English and Hindi
- Certification:
    1. **Certificate of completion from the industry, recognized globally**
    2. **The Government of Uttar Pradesh will also provide a separate certificate of completion to students under the AI Pragya initiative.**
- Cost: **Free of cost for all participants.**

Benefits to Students

- Access to a globally recognized co-branded certificate.
- Special certificate from the Government of Uttar Pradesh for completing the program
- Exposure to real-world AI use cases across sectors
- Career guidance and mentorship from EY professionals
- Enhanced AI, employability, and job-readiness skills to strengthen profile
- Access to a database of websites and resources to search for additional learning or employment opportunities

Support requested from the Departments. Of Education:

- Request issuance of an official circular to all the educational institutions encouraging participation in the AI Skills Passport Program.
- Request the Department to appoint a single point of contact (SPOC) at the state level to coordinate the execution and monitor progress of the program.
- Seek support in disseminating information about the program through official social media channels and digital outreach groups for wider visibility.

Support Requested from Institutions:

- Nominate one faculty coordinator.
- Arrange the venue and the projector/screen for the offline session
- Facilitate student mobilization and communication
- Follow up with students for course completion

Support Provided by AI Pragya Team & 1M1B:

- Trained facilitators to conduct orientation workshops
- Access to the course platform and WhatsApp support groups
- Learning plan and reminders for certification
- Organizing expert sessions with Industry mentors
- Periodic progress tracking and institutional updates